

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 256/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
शंकरराम पुत्र मंगलाराम जाति भील निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.मांगाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 2.खेताराम पुत्र हीराराम जाति भील निवासी इन्द्रोही तहसील रामसर व जिला बाड़मेर 3.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—


- 1 श्री देवीसिंह महेचा,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- 2.श्री अचलाराम चौधरी, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 01 व 3 एकतरफा।

आदेश

दिनांक—29.11.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की ओर से मूलवाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत कर विवादित भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 1.7326 हैक्टर व खसरा संख्या 1686/37 क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टर भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें बाबत आशय की इस्तदुआ चाही गई। जिस पर प्रार्थी का आवेदन पत्र




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
29.11.2022

पर एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर आदेश दिनांक 28.7.2022 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी गई कि विप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काशत में हस्तक्षेप दखलदान्जी नहीं करे व मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी करवाई गई थी। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री अचलाराम थोरी की ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया और प्रार्थी के आवेदन का पदवार जबाव पेश कर प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। शेष विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

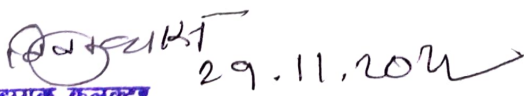
3. वकील प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 02 वकील की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये थे कि वादी/प्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश जारी करने हेतु पेश किया। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 1.7326 हैक्टर व खसरा संख्या 1686/37 क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टर भूमि अवस्थित है, जिसमें खसरा संख्या 36 में प्रार्थी का 77/274 हिस्सा व खसरा संख्या 1686/37 में 11/21 हिस्सा है और प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार भूमि पर रहवासीया ढाणी, पानी के टांके व मवेशी के लिए बाड़े इत्यादि बनायें हुए हैं। प्रार्थी द्वारा कभी भी आम मुखयारनामा विप्रार्थी संख्या 01 मांगाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है, बल्कि फर्जी इकरारनामा मांगाराम द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए धनराज व अन्य से मिलकर नोटेरी करवाया गया, जिस पर सभी पृष्ठों पर अगुठा अगुलियों के निशान प्रार्थी के किये हुए नहीं हैं एवं न ही प्रार्थी द्वारा साक्षीगण

 29.11.2022

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

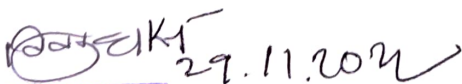
के समक्ष कभी भी आम मुख्यारनामा तस्दीक किया गया। जिससे मांगाराम किसी प्रकार का मुख्यारनामा नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 ने फर्जी तरीके से तैयार मुख्यारनामा के आधार पर विवादित भूमि का अवैध बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया। जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि को बेचान करने का विप्रार्थी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मिलीभगत करतें हुए मुख्यारनामा फर्जी तैयार करवाया गया और उक्त फर्जी मुख्यारनामा के आधार पर अवैध बेचान पत्र भी उप पंजीयक पचपदरा कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया गया। जिसकी प्रार्थी द्वारा कभी भी इस प्रकार का मुख्यारनामा खास विप्रार्थी संख्या 01 क पक्ष में नहीं लिखा गया था। लेकिन विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ धोर अन्याय किया गया है। प्रार्थी की ओर से फर्जी मुख्यारधारक वगैरा के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जा रही है। बेचानपत्र में साख देने वाले व्यक्ति श्री नारायणसिंह द्वारा प्रार्थी की भूमि को हड़प करने की नियत से ही अपने गांव के व्यक्ति के नाम बेचानपत्र पंजीबद्ध करवाया गया है। जबकि विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है और प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन गलत बेचानपत्र के आधार विप्रार्थी पक्ष प्रार्थी को मौके पर कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करने व मौका स्थिति को रद्दोबदल करने पर उतारू है और धमकिया दी जा रही है प्रार्थी की हक हिस्से की भूमि को आगे ओर अजनबी क्रेताओं को बेचान कर दी जावेगी। यदि इसमें सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और भविष्य में भी इसकी भूरपाई नही होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

05. इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 02 की बहस थी, कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण वाद खारिज योग्य है। जिस कारण आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अनुसूचित जनजाति पर

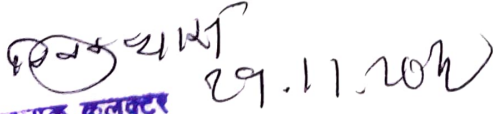

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पैतृक सम्पत्ति के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी स्वयं ने स्वेच्छा से विप्रार्थी संख्या 01 के हक में खास मुख्तयारनामा निष्पादित किया गया, उस पर प्रार्थी के अगुष्ट निशान हैं। प्रार्थी द्वारा निष्पादित आम मुख्तयारनामा को किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत कर, न्याय निर्णीत नहीं किया गया है, आम मुख्तयारनामा के जरिये प्रार्थी ने अपने समस्त हक, हित, अधिकार मुख्तयारधारक को दिये, जिसके द्वारा ऐसे विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए विवादित भूमि को बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को किया गया। जो कि एक प्रकार से वैध पंजीबद्ध दस्तावेज है और वक्त खरीद से आदिनांक तक विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा काश्त चला आ रहा है और पंजीबद्ध दस्तावेज की विधिक की जांच राजस्व न्यायालय को नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 ने सप्रतिफल भूमि खरीद की और तयशुदा प्रतिफल की राशि अदा की, जो प्रार्थी के अधिकृत द्वारा प्राप्त की, जो उससे प्रार्थी ने प्राप्त की। बेचाननामा फर्जी होने का कथन गलत है, नामान्तकरण से हको का सृजन नहीं होता है, हक हित अधिकारों का अन्तरण पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से होता है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखते हुए तर्क दिये कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर वाद व आवेदन पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जबकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी की ओर से अधिकृत मुख्तयारधारक से सप्रतिफल राशि अदा कर पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा अदालत को वास्तविक तथ्यों से गुमराह करते हुए स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जिसका प्रार्थी हकदार भी नहीं है और स्थगन आदेश जारी होने के कारण विप्रार्थी संख्या 02 को क्षति हो रही है। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 02 विवादित भूमि का खातेदार है और खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बनते हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चा आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व सलंगन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि

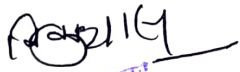

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोत्रा

के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 36 व 1686/37 भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश पारित हो रखा है। न्यायालय को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त योग्य है। इसके लिए प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीन बिन्दुओं के आधार पर तय होगा। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा कभी भी आम मुख्त्यारनामा विप्रार्थी संख्या 01 मांगाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है, बल्कि फर्जी इकरारनामा मांगाराम द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए धनराज व अन्य से मिलकर नोटेरी करवाया गया, जिस पर सभी पृष्ठों पर अंगुठा अगुलियों के निशान प्रार्थी के किये हुए नहीं है एवं न ही प्रार्थी द्वारा साक्षीगण के समक्ष कभी भी आम मुख्त्यारनामा तस्दीक किया गया। जिससे मांगाराम किसी प्रकार का मुख्त्यारनामा नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। प्रार्थी की ओर से आम मुख्त्यारनामा पर उठायें गये उजर एतराज मानने योग्य नहीं है। क्योंकि आम मुख्त्यारनामा की वैधता की जांच करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए सक्षम है और विवादित भूमि का रजिस्टर्ड बेचानपत्र के आधार पर बेचान हुआ है और बेचानपत्र के आधार पर विप्रार्थी संख्या 02 के विवादित भूमि में हक हकूक पैदा हुए हैं। खरीददार को स्थगन आदेश से पांबद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम द्विष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है और जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, वह भी विप्रार्थी के पक्ष में बनता है। क्योंकि मूल विवाद प्रार्थी की खातेदारी में दखलदान्जी नही करने बाबत है, जब प्रार्थी की ओर से अधिकृत मुख्त्यारधारक द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचानपत्र के भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया है, अब प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई हक हकूक पैदा ही नहीं होते हैं। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध बेचानपत्र को शून्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी विप्रार्थी के पक्ष में बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न

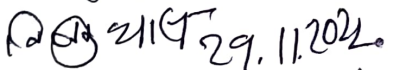

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोत्सा

है, वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंजीबद्ध बेचानपत्र के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई है और पंजीबद्ध बेचानपत्र होने के उपरांत भी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अर्जन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्रार्थी की ओर से सारहीन तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जो कि स्थगन आदेश जारी नहीं रह सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बनते हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 निरस्त योग्य होने एवं मूल आवेदनपत्र 212 सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

7. लिहाजा प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.7.2022 को निरस्त कर प्रार्थी का आवेदनपत्र खारिज किया जाता है।


(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
29.11.2022